दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा दुकानों की बिक्री

2903. **श्री सूरज प्रसाद** : क्या **शहरी विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा 1 जनवरी, 1985 से 31 मार्च, 1987 तक बेची गई दुकानों की सबसे ऊंची बोली लगाने वाले व्यक्तियों के नाम क्या हैं तथा बेची गई दुकानों की संख्या सहित उनके क्षेत्रों का ब्यौरा क्या है ;

(ख) उपर्युक्त अवधि के दौरान कितने मामलों में बोली लगाने वाले व्यक्ति एक महीने में दुकानों की पूरी धनराशि जमा कराने में असफल रहे तथा उनके नाम व पते क्या हैं ;

(ग) क्या उपर्युक्त अवधि में कुछ मामलों में पूरी धनराशि बोली की अवधि के पूरे होने से एक महीने के समाप्त होने के बाद जमा करा दी गई है और अब दिल्ली विकास प्राधिकरण धनराशि का 25 प्रतिशत का जुर्माना लगाकर बाकी धनराशि को वापस कर रहा है और दुकानों के आवंटन को रद्द कर रहा है, यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(घ) क्या सरकार ऐसे मामलों में दंड देकर और दुकानों के आवंटन को रद्द न करके इन दुकानों का कब्जा देने पर विचार करेगी ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) से (घ). दिल्ली विकास प्राधिकरण से प्राप्त सूचना की जांच की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

Basic amenities for Abul Fazal Enclave, Okhla, Delhi

2904. SHRI SHAMIM AHMED SIDDIQI: Will the Minister of URBAN DEVELOPMENT be pleased to state:

(a) whether it is a fact that Abul Fazal Enclave, Okhla, South Delhi having a population of more than 20,000 existing since 1979 is still unapproved and without civic amenities like road, sewer, drainage, protected water supply, school, dispensary, Post office. Fair Price Shop, scavenging facilities; etc.;

(b) if so, what are the reasons therefor; and

(c) what action has been taken by Government to ameliorate the living conditions of the citizens of this colony?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF URBAN DEVELOPMENT (SHRI DALBIR SINGH):, (a) to (c) This colony came into existence after February-June, 1977. Therefore, it could not be regularised as per Government policy. Furthe: civic amenities are provided only aft ir a colony is regularised.

चीनी का आयात

2905. **श्री शिव कुमार मिश्र** : क्या **खाद्य और नागरिक पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले 3 वर्षों में कितनी चीनी का आयात किया गया और उस पर कितनी विदेशी मुद्रा का प्रतिवर्ष व्यय हुआ ;

(ख) आयात की जाने वाली चीनी में प्रतिवर्ष कितनी कमी की जाती है और उसका मूल्य क्या है ;

(ग) भारतीय राज्य व्यापार निगम ने किस मूल्य पर भारतीय खाद्य निगम को चीनी बेची तथा भारतीय राज्य व्यापार निगम ने इसमें अपने प्रशासनिक व्यय को जोड़ा है ; यदि हां तो उसका प्रति मीटरी टन ब्यौरा क्या है ; और

(घ) भारतीय राज्य व्यापार निगम द्वारा पिछले तीन वर्षों के दौरान अपनी उप एजेन्सी इंडियन शुगर इंडस्ट्री एक्सपोर्ट कारपोरेशन को प्रति मीटरी टन कितना प्रशासनिक एवं हैंडलिंग व्यय दिया गया ?